>

Title: Need to provide financial support to dairy farms in Betul Parliamentary constituency, Madhya Pradesh under Dairy Entrepreneurship Development Scheme.

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल): केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2009 से 2012 तक डेयरी एन्टरेप्रोन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम (डी.ई.डी.एस.) योजना में प्रतिवर्ष 150 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इस योजना में दुग्ध उत्पादकों को 5 लाख तक के प्रस्तावों पर नाबार्ड द्वारा 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा नाबार्ड के निर्देशन पर कोई भी प्रकरण स्वीकृत नहीं किया गया।

मेरा संसदीय क्षेत्र बैतूल (मध्य प्रदेश) जोकि आदिवासी बाहुल्य हैं, यहां पर लोगों के पास कृषि योग्य भूमि उपलब्ध नहीं हैं। यहां के लोग वनोपज एवं दुग्ध उत्पादन पर निर्भर हैं। यदि इस योजना को शीघ्र किए जाने हेतु बैंकों को निर्देशित किए जाने का कष्ट करें जिससे कि आदिवासी बाहुल्य जिले को इसका लाभ मिल सके।

मैं आशा करूंगी कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस योजना का लाभ दुग्ध उत्पादकों को मिल सके।